शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Year -1
Vol -12
October
2024

वर्तमान भारतीय गठबंधन सरकार : चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

डॉ. वंदना तिवारी
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर

सार

भारत जिस भौगौलिक क्षेत्र में बसा है वह पर्वत, पठार, मैदान रेगिस्तान तथा तटीय क्षेत्र में विभाजित है अत: जहाँ जलवायु में विविधता हो तो वहाँ के सामाजिक मूल्यों और परंपराओं में विविधता दिखाई देना स्वाभाविक ही है। ऐसी परिस्थिति में जाहिर है कि हर क्षेत्र की समस्याएँ और निदान की प्रवृत्ति और प्रविधि भी अलग होगी तथा वहाँ की समस्याएँ भी एक केन्द्रीय शक्ति द्वारा हल नहीं की जा सकती है, इन्हीं समस्याओं के निराकरण और अभिजात्मवादी राजनीतिक संस्कृति की उदासीनता के फलस्वरूप जिस तरह क्षेत्रिय दलों एवं समूहों का उदय हुआ उन दलों ने समय के चक्र के साथ केन्द्रीय राजनीतिक प्रवृत्ति को ही बदल दिया जिसका परिणाम था एक दल का (सत्ता में) बहुमत में न आ पाना। इसी प्रवृत्ति ने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़ने एवं राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने पर मजबूर कर दिया। इन गठबंधनों से बनने वाली सरकारों ने राजनीतिक स्थिरता को तोड़ने का काम किया गठबंधनात्मक संस्कृति की परम्परा जिसे लेकर आज की मोदी सरकार भी सचेत होकर चल रही है जिसे क्षेत्रीय दलों की जायज और नाजायज मांगों को ध्यान में रखते हुए जनता के विश्वास पर भी खरे उतरने के साथ-साथ भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना ही सबसे अधिक चुनौतिपूर्ण कार्य बन गया है जो इस सरकार के सभी घटकों की राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास से ही संभव हो सकता है।

शब्द कुंजी

गठबंधन सरकार, क्षेत्रीय दल, अभिजात्मवादी संस्कृति, गठबन्धात्मक संस्कृति, परम्परावादी घटक, विविधता, लोकतंत्र।

भूमिका

जब कोई एक दल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो वह अन्य दलों के सहयोग एवं समर्थन से सरकार बनाने का प्रयास करता है ऐसी बनी सरकार को गठबंधन सरकार की संज्ञा दी जाती

है कुछ सरकारें अपने दल का निर्माण चुनाव पूर्व ही कर लेती है तो कुछ चुनाव के उपरांत। ऐसे गठबंधन सरकार की परपंरा के विकास के कई महत्वपूर्ण पहलू है जो भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत ही प्रारम्भ हो गये थे जिसका पहला उदाहरण 1953 में आध्रप्रदेश की सरकार प्रस्तुत करती है हालांकि यह सरकार मात्र 13 महीने तक ही चल सकी। इसके बाद राज्य में ही नहीं केंद्र में भी अस्थिर सरकारों की झड़ी लग गयी। 1975 में इंदिरा गांधी आयरन लेडी की भूमिका में नजर आ रही थी जिसका परिणाम 1977 के निर्वाचन में कांग्रेस को चुकाना पड़ा और भारत में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी।

पुन: जो सरकार बनी वह अलग-अलग विचाराधारा के दलों से बनी थी जिसका जनतापार्टी से मतभेद उत्पन्न हो गया और मोरार जी देशाई की सरकार गिर गयी इसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधान मंत्री बनाया गया लेकिन यह सरकार भी दलीय अंतविरोधों के कारण अधिक चल नहीं पायी। 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी को पुन: सत्ता संचालन का अवसर प्राप्त हुआ, 1989 में वी.पी. सिंह संयुक्त मोर्चा वाली गठबंधन सरकार बनी जो 11 महीने ही चल पायी, 10 नवबंर 1990 में चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार बनी उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी, यह सरकार में आपसी महत्वाकांक्षा की भेट चढ़ गयी। जून 1991 में पी. बी नरसिम्हा राव की स्थायी सरकार बनी जिसके बाद 1996 से लेकर 1999 तक एक के बाद एक सरकारें बनी और गिर गयी जिसका खामियाजा देश को ही नहीं बल्कि भारतीय समाज को भी उठाना पड़ रहा था। अब स्थिति यह थी कि कोई सरकार 13 दिन चल रही थी तो कोई 13 महीने, दूसरे लगातार चुनाव से देश आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था, क्षेत्रीय दल सत्ता की लालच में एक गठबंधन की तोड़कर दूसरें गठबंधन बनाकर सरकार में घुसना चाहती थी। जैसे यह कोई खेल हो गया हो ऐसी स्थिति में सिद्धांत विहीन और मूल्य विहीन सरकार किसी सामूहिक उत्तरदायित्व या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को संभाल नहीं पा रही थी साथ ही प्रधानमंत्री का पद अपने गरिमा को समाप्त कर चुका था। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा ने राष्ट्रीय दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्थायी सरकार नहीं बनी तो कोई भी दल न तो अपनी राष्ट्रीय पहचान बना पायेगा और न ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पायेगा क्योंकि भुखमरी, बेरोजगारी, महँगाई जैसी समस्याएँ अपना मुँह बाये जब खड़ी हो जाती थी तो सरकार के औचित्य और उत्तरदायित्व पर प्रश्न खड़ा कर देती थी। विश्व समूह भी भारत को हिदायत देने के लिए कोई न कोई राग अलापने लगता था इन समस्याओं का अंत सिर्फ स्थिर सरकारों की स्थापना से ही संभव था।

1999 में 24 दलों के साथ भाजपा नीत राजग की गठबंधन सरकार बनायी जिसने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के साथ-साथ घटक दलों को साथ लेकर संतुलन बनाने का एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जो आगे की सरकारों को अन्य क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने के लिए सीख भी दिया। इसी का परिणाम था कि भारत ने एक वैश्विक प्रतिमान स्थापित करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में UPA का निर्माण किया जिससे घटक दलों को एक राष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ इस गठबंधनात्मक संस्कृति ने 2004 के चुनाव से लेकर 2009 तक के चुनाव में अपनी एक अलग पहचान बनायी। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ था लेकिन वी.जे.पी. ने घटक दलों को साथ में लेकर गठबंधन के सिद्धांत को बखूबी निभाया।

2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें प्राप्त की गठबंधन को 293 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस की INDIA गठबंधन 234 सीटें ही प्राप्त कर सकी ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA ने सरकार तो बना ली लेकिन सबसे बड़े घटक दल TDP और जदयु की महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप अन्य दलों की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष सरकार स्थायित्व का गूढ़ प्रश्न पुन: उत्पन्न हो गया है। क्योंकि तेलगू देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिव सेना तथा लोक जन शक्ति पार्टी जहाँ सत्ता में अपने लिए पद आरक्षित रखना चाहते थे वहीं जनता दल सेल्यूलर, राष्ट्रीय लोकदल जन सेना पार्टी एवं अन्य भी लाभ से वंचित नहीं रहना चाहते वे यह जानते है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के आम चुनाव परिणाम की तरह मजबूत स्थिति में नहीं है। चुनाव परिणाम के उपरांत सभी प्रिंट एवं इलेक्टॉनिक मीडिया इसी कपास में थे कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नितिश कुमार कोई-न-कोई अडंगा जरूर लगायेंगे, दूसरे टी.डी.पी. जो इस गठबंधन में बड़ा घटक थी जरूर बड़े पदों की माँग करेगी। लेकिन नरेन्द्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अभी दो प्रमुख कैबिनेट मंत्रालय शीर्ष घटक दलों को प्रदान कर उन्हें संतुष्ट कर दिया लेकिन अभी भी अन्य घटक दलों की महत्वाकांक्षा संतुष्ट नहीं हुई है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी कमजोर नहीं हुआ है दूसरे भारत की वैश्विक पहचान बनाने में मोदी सरकार अपनी अहम भूमिका निभाने में कामयाब भी रही है चाहे वह पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में हो या विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र रूस और अमेरिका के संदर्भ में हर स्तर पर सरकार अंतराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मंचों पर न केवल अपनी पहुंच बनाने में सफल हो रही है बल्कि अपनी बात वैश्विक मंच पर रखने में भी सफल रहा है। आज विश्व जिस

प्रौद्योगिकी के साथ आर्थिक दौर से गुजर रहा है ऐसे में भारत न केवल वैश्विक निवेश का स्थल बन सकता है अपितु वैश्विक विनिवेशक एवं निर्यातक भी बन सकता।

हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोगों ने एक बार फिर चुनावी विश्लेषकों की भविष्यवाणी को झूठा होते हुए देखा इसका सीधा सा अर्थ है कि अब चुनाव संगठनात्मक ताकत से ही जीते जा सकते है क्योंकि अति- आत्मविश्वास किसी भी दल को सत्ता नहीं दिला सकते उदाहरण स्वरूप लोक सभा चुनाव में भाजपा का यह नारा कि अब की बार चार सौ पार तथा हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व जाट फैक्टर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का नारा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष स्थायी सरकार चलाने और जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए निम्न लिखित चुनौतियाँ होगी।

- संगठन को स्थायी बनाने की चुनौतियां
- उनकी मांगों को पूरा करने की चुनौतियां
- अपने गठवधनात्मक मूल्यों को बनायें रखने की चुनौतिया।
- राज्यों में बनी सरकारों या बनने वाली सरकारों में क्षेत्रीय घटकों को उचित अवसर देनें की चुनौतियां
- सम्वैधानिक मूल्यों के साथ सरकार के संचालन की चुनौतियां।
- योजनाओं, परियोजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों को संतुलित रूप में क्रियान्वित करने की चुनौतियां
- समाज के दलित एवं वंचित लोगों को उचित अवसर प्राप्त कराने की चुनौतियां
- देश के विकास में वाधक अवरोधों को पता लगाकर उसका निदान करने की चुनौतियाँ।
- औद्योगिक विकास के साथ निजी एवं सार्वजनिक संतुलन की चुनौतियां
- भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, एवं भुखमरी के निवारण की चुनौतियां
- न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के आपसी समन्वयन की चुनौतियां वैश्विक स्तर पर भारतीय पहचान को बनाये रखने की चुनौतियां

शोध साहित्य SHODH SAHITYA
INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL
(समसामयिक विषयों पर केंद्रित बहुविषयक मासिक ई-शोध पत्रिका)
E-ISSN 2584-2447
Impact Factor – SJIF 2024 = 3.621
Year -1
Vol -12
October
2024

उपर्युक्त चुनौतियों को पार पाने के लिए सरकार के समक्ष अपार संभावनाएं भी है और सक्षमता भी है क्योंकि भारत की 60% से अधिक आबादी कार्यशील आबादी है और यह विश्व का सबसे युवा देश भी है जहाँ कौशल विकास की अपार संभावनाएं है जिससे सरकार न केवल रोजगार उत्पन्न कर सकती है अपितु उत्पादन में बढ़ोत्तरी करके आर्थिक संकट से देश का निदान भी दिला सकती है। वहीं वैश्विक निवेश को आकर्षित कर भारत को वैश्विक भी बना सकती है जिसके साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिक चिकित्सा एवं तकनीकी प्रणाली का विकास कर लैव –टू लैंड के लक्ष्य के प्राप्त कर अन्नदाता को भी लाभन्वित कर सकती है।

यही नहीं भारत सरकार इजराइल – इरान रूस-यूक्रेन एवं विश्व के अन्य मतभेदों में अपने मूल्यों वसुधैव कुटुम्बकम को प्रसारित कर एक अद्वितीय पहचान भी स्थापित कर सकती है। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 3.0 अपने चुनौतियों को पार करने में सक्षम है वशर्ते संगठनात्मक मूल्य के सिद्धांत में किसी प्रकार का फेरबदल साधन की पवित्रता के साथ होने चाहिए यही पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता ही सरकार को स्थापित प्रदान करेंगे जिसे यह गठबंधन सरकार बखूबी निभा रही है यही कारण है कि कांग्रेस आज भी ग्राउंड गेम का मुकाबला इस (सरकार) गठबंधन से नहीं कर पा रही है। यदि जनता का विश्वास एवं आधुनिक राजनीतिक संस्कृति के सिंद्धातों का प्रसार किया जाए जो जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र सम्प्रदाय से उठकर विकास के नाम पर मतदान हो तो इसका उचित प्रयास ही भारत को अलौकिक स्वरूप प्रदान करेगा जो भारत को स्थिर, मजबूत एवं विकासशील से विकसित रूप में परिवर्तित कर में अहम योगदान प्रदान करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एन सी. साहनी - कोलिएशन पॉलिटिक्स इन इंडिया 1971
2. डॉ. किरण झा - भारतीय राज व्यवस्था 1998
3. रजनी कोठारी भारत में राजनीति
4. दैनिक भास्कर, सागर संझार, 11 अक्टूबर 2024 राजदीप सरदेसाई
5. डॉ. एम. पी. राय एवं डॉ. आर. एम. द्विवेदी भारतीय राजनीति व्यवस्था
6. राजू पंवार, आरजू मिश्रा, भारतीय शासन और राजनीति